अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 03, (July-Sep 2026)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र से ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन
विश्लेषणात्मक–अध्ययन

पंकज कुमार, शोध छात्र,
शासकीय पीजी कालेज, मुरैना
प्रो0 राजवीर सिंह किरार, विभागाध्यक्ष,
शासकीय पीजी कालेज, मुरैना

शोध सार :–

एक बेहतर जीवन जीने की ललक हर किसी के मन में होती है। एक अच्छा जीवन स्तर, सुख सुविधाओं व संसाधनों को जुटाने के लिये मनुष्य शुरू से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहा है। एक बेहतर कल की आकांक्षा लिये व्यक्ति सपरिवार बोरिया बिस्तर लेकर महानगरों की ओर निकल जाता है परन्तु यह उत्प्रवासन उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष अत्यधिक हो जाने के कारण ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़ देता है व देश के सामाजिक आर्थिक ताने–बाने की अस्त व्यस्त कर देता है।

गांवों से शहरों की ओर आने वाली एक बड़ी आबादी ने शहरी ढांचे को अस्त व्यस्त कर दिया व शहरी योजनाकारों के समक्ष अप्रत्यशित आबादी के नगर नियोजन की समस्या उत्पन्न कर दी है व शहरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का विस्तार हुआ। इस आबादी को शहरों में गुणवत्ताहीन, निम्न जीवन स्तर व्ययीत करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार, पानी, उद्योग धंधों का अभाव है जिससे यहां मजबूरीवश होने वाले पलायन की बडी विकट समस्या है। इस क्षेत्र से लोगों के झुण्ड के झुण्ड रेलवे स्टेशनों पर महानगरों की ओर जाते हुये देखे जा सकते हैं। गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए 'मनरेगा' व 'पूरा' (प्रोवाइडिग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया) जैसी अनेक योजनाये क्रियान्वित की गयी है जिनसे शहरीकरण की गति समाप्त तो नहीं हुई, परन्तु फिर भी इसकी तीव्रता में कमी अवश्य आयी है।

ग्रामीण जनसंख्या में उत्तरोत्तर कमी व शहरी जनंसख्या में उत्तरोंत्तर वृद्धि जनसांख्किीय आकड़ों से परिलक्षित होती है जिससे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों का जननांकीय अनुपात प्रतिकुल हुआ है।

उद्देश्य :–प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र में से लगातार मजबूरीवश होने वाले पलायन के कारण महानगरों में बढती शहरी आबादी व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में घटती ग्रामीण जनसंख्या को निरूपित कर ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन के कारणों का पता लगाना है। पलायन से शहरों की आधारभूत संरचना पर उत्पन्न दबाव, प्रवासन की समस्यायें, ग्रामीण जनसंख्या में कमी आने से गांवों का विकास कैसे प्रभावित होता व शहरीकरण से क्या–क्या समस्याओं का जन्म होता है आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 03, (July-Sep 2026)

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र से ग्रामीण जनसंख्या के बढ़ते पलायन व महानगरों में बढते शहरीकरण को रोकने के लिये आवश्यक उपायों का भी वर्णन किया गया है।

अध्ययन व विश्लेषण :–प्रस्तुत विश्लेषण में भारत के अति पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के बेहद पिछडे जिले, जिला जालौन को जनसांख्यिकी अध्ययन के लिये चुना गया जो कि देश के शीर्ष 100 पिछड़े जिलों में शामिल है। जनपद–जालौन का कुल क्षेत्रफल 4565 वर्ग मीटर है व इसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 16,89,974 है। जालौन जिले के विगत 100 वर्षो के ग्रामीण–नगरीय जनसंख्या के आंकड़े निम्नतालिका से प्रदर्शित है।

:– जालौन जिले की ग्रामीण नगरीय जनंसख्या का विश्लेषण :–

वर्ष	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत में)	नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)
1911	431158	383365	47793	88.90%	11.10%
1951	553572	465130	88442	84.03%	15.97%
2001	1454452	1113926	340526	76.59%	23.41%
2011	1689974	1271074	418900	75.21%	24.79%

इन आंकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि 1911 से 2011 तक की समयावधि में ग्रामीण जनसंख्या में उत्तरोत्तर कमी दर्ज की जाती रही है व ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात घटता जा रहा है जहां वर्ष 1911 में इस जिले में कुल 88.90% जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी वही वर्ष 2011 तक आते–आते केवल 75.21% जनसंख्या ही ग्रामों में अपना आवास बनाये है।

गांवों से शहरों की ओर जनसख्या का प्रस्थान केवल जालौन जिले तक ही नही बल्कि पूरे बून्देलखण्ड एवं राष्ट्र के लिये ज्वलन्त समस्या बनने की स्थिति में है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर जननांकीय आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो पायेगे कि 1901 में ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का 89.2% थी जोकि 1951 में घटकर 82.7% व 2011 की जनगणना में 68.8% ही रह गयी। 2011 की जनगणना के दौरान देश की ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 12%रही वहीं शहरी जनसंख्या 31.8% की दर से बढ़ी। आजादी के बाद यह पहली बार है कि ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा शहरी जनसंख्या निरपेक्ष तौर पर अधिक तेजी से बढ़ी है जो कि ग्रामीण–नगरीय जनसंख्या के बिगड़ते अनुपात को दर्शाता है। इससे शहरों में उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बडा है व प्रवासी लोगों को शहरों में गुणवत्ताहीन जीवन व्यतीत करना पडता है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 03, (July-Sep 2026)

राष्ट्रीय स्तर पर शहरी व ग्रामीण जनसांख्यिकी वितरण

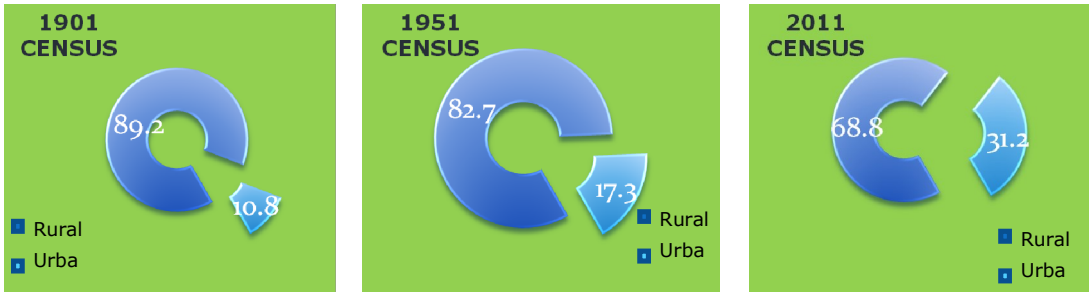

ग्रामीण जनसंख्या की शहरों की ओर इस पलायनवादी प्रवृत्ति ने शहरों में अनेकानेक समस्याओं को जन्म दिया। बुन्देलखण्ड में हालात और भी भयावह है जहां गांव के गांव सूने होते जा रहे है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र से मुम्बई, गुजरात, दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें यथा कुशीनगर एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, चित्रकूट सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस, बांद्रा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से मजदूर बिस्तर–बोरियां सहित बेहद अमानवीय परिस्थितियों मे महानगरों की ओर पलायन कर रहे है। ऐसे परिवार केवल तीज–त्योहारों पर ही गांव आते जिससे ग्रामीण नगरीय जनसख्या का संघटन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

ग्रामीण जनसंख्या के पलायन के कारण :–ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर आकर्षित होने का प्रमुख कारण जनसख्या में तीव्र वृद्धि व रोजगार का अभाव है। इसके अतिरिक्त संसाधनों की कमी, कुटीर उद्योगों का पतन, ऋणग्रस्तता, सामाजिक भेदभाव आदि पलायनवादी प्रवृत्ति को बढ़ाते है। औद्योगिक क्रांन्ति से शहरों में रोजगार के अवसर बढ़े हे। 'किग्सले डेविस' ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ''औद्योगिक विकास तथा नगरों में आगंतुकों की संख्या में वृद्धि के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है।''

ग्रामीण जनसंख्या के पलायन के निम्न कारण देखे गये :–

1. गांवों में रोजगार का अभाव
2. गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी
3. ऋणग्रस्तता
4. सामाजिक भेदभाव व छुआछूत
5. नगरीय चकाचौध का आकर्षण
6. गांवों में अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा का अभाव
7. कुटीर उद्योगों का पतन
8. उन्नत जीवन व अधिक मजदूरी की आशा
9. कृषि जोतों का सीमित होना
10. बाढ़, सूखा व अन्य प्राकृतिक विपदा

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 03, (July-Sep 2026)

ग्रामीण जनसंख्या के शहरों में पलायन के दुष्परिणाम :–ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासित जनसंख्या अनेकानेक समस्याओं को जन्म देती है। व्यक्ति को प्रवास के दौरान अपनी पैतृक संस्कृति का शहरी संस्कृति से तादात्य करने के लिये संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शहरों में स्थायी रोजगार व आश्रय न मिलने पर चोरी, लूट, राहजनी आदि अपराधों की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति देखी जाती है। शहरी मायाजाल व्यक्ति को नैतिक रूप से खोखला करने में सहायक होता है। वेश्यावृत्ति, मद्यपान, जुआ खेलना आदि घृणित कृत्य शहरों में बिना किसी सामाजिक या पारिवारिक भय के किये जाते है। उचित आवासीय सुविधायें न मिलने से मालिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि होती है व प्रवासी मजदूरों के लिये अस्वास्थ्य कर जीवन दशायें व गुणवत्ताहीन जीवन स्तर उपलब्ध होता है। स्वच्छता का अभाव रोगों को आमंत्रण कर इनको बीमार बनाता है।

प्रतिभाशाली ग्रामीणों व क्षमतावान मजदूरों युवाओं के गांव छोड़ने से गांवों की सम्यक देखभाल नहीं हो पाती व गांव का विकास अवरूद्ध होता है। शहरों में भी योजनाकार अनुमान नहीं लगा पाते कि कब कितने लोग शहर में आ जायेगे।

समाधान :–ग्रामीण नागरिकों के शहरों की ओर बढ़ते पलायन को रोकने के लिये पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने सुझाया था कि क्यों न शहरों की सारी सुविधाएं गांवों में ही उपलब्ध करा दी जाए। इनकी प्रेरणा से 'पूरा' मिशन (प्रोवाइडिग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया) 2002 में शुरू किया गया था। 'पूरा' के अन्तर्गत गांवो का विकास पीपीपी माडल पर करने की योजना चलायी गयी। इसके अतिरिक्त 'मनरेगा' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम) योजना से ग्रामीण क्षेत्राों से पलायन की तीव्रता में कमी आयी है। गांवों से शहरों की ओर बढ़ती आबादी को रोकने के लिये खेती, पशुपालन को सम्पन्न व लाभकारी बनाना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए निम्न उपाय किये जा सकते है :–

1. छुआछूत व भेदभाव रहित ग्रामीण समाज की स्थापना
2. गांवों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता
3. कुटीर उद्योगों का विकास
4. ग्रामीण रोजगार के अवसरों का सृजन
5. स्वयं सहायता समूहो की स्थापना
6. ग्रामीण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
7. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
8. मनरेगा, पूरा जैसी योजनाओं का पारदर्शितापूर्वक क्रियान्वयन
9. ग्रामीण क्षेत्रों के दायरें में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
10. ग्रामीण–कस्बाई क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग की उपलब्धता

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 03, (July-Sep 2026)

निष्कर्ष एवं सुझाव :–हमारे यहां शहरों की ओर प्रस्थान विकास पर आधारित न होकर गरीबी व बेरोजगारी पर आधारित है। गांवों से पलायन के द्वारा लोग एक बेहतर व सुखमय जीवन जीने का जो सपना देखते वह शहरी जटिलतओं में टूट जाता है। ये प्रवासी नागरिक सम्पन्न, शक्तिशाली व धनी लोगों की जीवन शैली सुखी बनाने के उपकरण मात्र बनकर शहर में दयनीय जीवन यापन करते है, लेकिन रोजगार की मजबूरी उन्हे गांवों में नहीं लौटने देती। पलायन केवल कार्यशील जनसंख्या का होता है व गांवों में आश्रित जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाता है।

पलायन के उजले पक्ष की ओर देखे तो पायेंगे कि शहर मे आकर ग्रामीणों का दृष्टिकोण व्यापक बनता व वे स्वयं को गांव या समुदाय से ऊपर उठकर देखने लगते। लोग जाति धर्म के संकीर्णता से मुक्त हो जाते है। गांवों से निकलने वाले बेहद मामूली व साधारण परिवारों के लोगों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया व सफलता प्राप्त कर विविध क्षेत्रों में शिखरों तक पहुंचे। गोरखपुर के छोटे से गांव से निकलकर सुब्रतराय सहारा ने सहारा साम्राज्य की नींव रखी तो वहीं गुजरात के छोटे से कस्बे से निकलकर नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमन्त्री की कुर्सी तक पहुंचे। यह शहरों में प्रवासित जनसंख्या की शक्ति ही थी जिस पर तत्कालीन गृहमन्त्री पी0 चिदम्बरम कहते थे कि हां, मैं महानगर में प्रवासी हूं।

गांवों में न तो मेहनती लोगों की कमी न ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, जरुरत तो बस गांवों में शहरी सुविधायें उपलब्ध कराने की है, जिससे शहरी चकाचौंध का आर्कषण कम हो सके, जरूरत है खेती, पशुपालन, बागवानी व कुटीर उद्योगों को लाभकारी बनाने की। यदि शहरों के बजाय गांव की जनसंख्या के पहुंच के दायरे में औद्योगिक विकास किया जाये, निकट के कस्बाई इलाकों में रोजगार का विस्तार किया जाये तो किसानों को नजदीक ही अपनी उपज का मूल्य प्राप्त हो सकेगा, वही शहरों के उपर से जनसंख्या का दबाव कम हो सकेगा साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कम हो सकेगा। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, जाति व्यवस्था जैसी समस्याओं के निराकरण के द्वारा गांवों से पलायन कम किया जा सकता है। गांवों के नजदीक स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षण संस्थान आदि की उपलब्धता से इस समस्या को कम किया जा सकता है।

संदर्भ :–

1. कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका, सितम्बर 2014 सूचना भवन, नई दिल्ली
2. www.updes.up.nic.in जिला सांख्यिकी पुस्तिका जनपद जालौन, वर्ष 2013 राज्य नियोजन संस्थान– उ0प्र0
3. www.censusofindia.gov.in प्राथमिक जनगणना सार– भारत
4. www.censusmp.gov.in ग्रामीण नगरीय जनसंख्या– 2011